



- द्वीप समूह में उपचुनावों के परिणाम घोषित— भाजपा ने तीन, कांग्रेस ने दो और निर्दलीय ने एक सीट पर जीत हासिल की।
- द्वीपसमूह के छात्रों के आंदोलन पर प्रशासन का आश्वासन—फीस नहीं सुविधाएं बढ़ेंगी।
- सरकार ने कल सूचना प्रौद्योगिकी—मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम, 2021 में संशोधन अधिसूचित किए हैं।
- डाइट की ओर से द्वीपों के सभी नौ शैक्षिक क्षेत्रों के लिए तीन दिवसीय FLN मेंटर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।



द्वीप समूह में हाल ही में संपन्न हुए उपचुनावों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। उप-चुनाव में भाजपा ने तीन सीट, कांग्रेस ने दो और एक में निर्दलीय ने एक सीट हासिल की। ग्राम पंचायत सदस्य (मधुपुर-6) से भाजपा की प्रत्याशी तरामणि हालदार को 137 वोट मिले, वहीं मायाबंदर जिला परिषद सदस्य पी. चंद्रवती को 1663 वोट प्राप्त हुए। ग्राम पंचायत सदस्य बकुलतला-3 के भाजपा प्रत्याशी महेश सिंह को 82 वोट, जबकि ग्राम पंचायत सदस्य मन्नारघाट-4 में कांग्रेस प्रत्याशी आशिक अली ने 69 वोट और ग्राम पंचायत सदस्य बम्बूपलाट-1 से बी पदमावती ने 94 वोट हासिल किए। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के वार्ड नम्बर 17 से वार्ड पार्षद निर्दलीय सदस्य ए. गणेशन को कुल 1056 वोट हासिल हुए।



नेताजी सुभाष चंद्र बोस उच्च शिक्षा संस्थान के घटक कॉलेजों के छात्रों की ओर से आंदोलन किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में छात्रों की मांगों पर विचार-विमर्श किया गया और प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है। प्रशासन ने कहा कि कॉलेज के वर्तमान शुल्क ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा। शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए फीस मामूली बनी रहेगी। घटक कॉलेजों से मौजूदा बुनियादी ढांचा वापस नहीं लिया जाएगा। कॉलेज अपने वर्तमान ढांचे के साथ काम जारी रखेंगे। इसके अलावा, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बुनियादी सुविधाओं को और बढ़ाया जाएगा। छात्रों को मिलने वाले वजीफे को बंद नहीं

किया जाएगा। द्वीप प्रशासन अपनी स्थापना के पांच साल बाद भी संस्थान को वित्त पोषित करना जारी रखेगा। वर्ष 2025–26 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के सहयोग से एक समझौता ज्ञापन के तहत परीक्षा और मूल्यांकन आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय को यूजीसी विनियम, 2023 के अनुसार NIRF और NAAC मान्यता प्राप्त होगी। 5 वर्षों के बाद संस्थान NAAC, NIRF, NBA रैंकिंग में भाग लेकर उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा प्रशासन ने कहा कि द्वीपों के भीतर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि छात्रों को बाहर न जाना पड़े। इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम को द्वीप समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना और छात्रों के लिए स्थानीय स्तर पर ही शोध गतिविधियों के नए रास्ते खोलना है।



कला एवं संस्कृति विभाग ने इच्छुक कलाकारों से पुनः आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नामांकन लोक या जनजातीय कला के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के लिए किया जाना है। ये आवेदन पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता के कार्यक्रम समिति के सदस्य के रूप में कलाकार के नामांकन हेतु मांगा गया है। कलाकारों का चयन पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और संस्कृति मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। इच्छुक कलाकार उपलब्धियों के विवरण सहित अपना बायोडाटा 24 फरवरी तक सेल्यूलर जेल परिसर स्थित कला एवं संस्कृति निदेशक के पते पर व्यक्तिगत या विभाग के मेल पर भेज सकते हैं।



बुनियादी ढांचे के विकास और क्षेत्रीय संपर्क को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, अंडमान निकोबार प्रशासन ने राज्य हाईवे नंबर 8 के 1.75 किलोमीटर लंबे हिस्से के सुधार के लिए 4.16 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। यह सड़क गुप्तापाड़ा जंक्शन से मंगलुटान जंक्शन को जोड़ती है। इस परियोजना से 3,722 से अधिक निवासियों को सीधा लाभ होगा और पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। इसमें 22 आरसीसी बॉक्स कलवर्ट का विस्तार, 02 नए आरसीसी बॉक्स कलवर्ट का निर्माण और आरसीसी रिटेंनिंग वॉल का निर्माण शामिल है। प्रशासन की सतत बुनियादी ढांचा विकास और समावेशी आर्थिक विकास से न केवल स्थानीय यातायात सुगम होगा, बल्कि पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।



सरकार ने कल सूचना प्रौद्योगिकी-मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम, 2021 में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस-एआई द्वारा निर्मित और आर्टिफिशियल सामग्री को औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को एआई द्वारा निर्मित या डीप फेक सामग्री को सरकार द्वारा चिह्नित किए जाने तथा न्यायालय के आदेश के बाद तीन घंटे के भीतर हटाना होगा। आधिकारिक अधिसूचना में डिजिटल प्लेटफॉर्मों को एआई लेबल या संबंधित मेटाडेटा को लागू होने के बाद हटाने या दबाने की अनुमति देने से भी रोक दिया गया है। नए नियम 20 फरवरी से लागू होंगे।



डॉ. एस. आर. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से द्वीप समूह के सभी नौ शैक्षिक क्षेत्रों के लिए तीन दिवसीय FLN मेंटर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य द्वीपों के स्कूलों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्रथाओं को मजबूत करना और मेंटर्स को प्रभावी, बाल-केंद्रित रणनीतियों की जानकारी प्रदान करना है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में राज्य शिक्षा संस्थान की प्राचार्या संगीता चंद, ने किया। उन्होंने बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्षों में मजबूत बुनियादी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षार्थियों के समग्र शैक्षणिक विकास के लिए साक्षरता और संख्यात्मकता में एक मजबूत आधार होना अनिवार्य है। इसे दौरान बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण, प्रभावी कक्षा रणनीतियाँ, शिक्षण-अधिगम सामग्री के उपयोग और बुनियादी कौशल का मूल्यांकन करने के बारे में बताया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी नौ शैक्षिक क्षेत्रों के मेंटर्स भाग ले रहे हैं। उनसे स्कूल और अंचल स्तर पर FLN कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा गया। कार्यक्रम का समापन आज होगा।



रायपुर, छत्तीसगढ़ में 16 से 22 मार्च तक नेशनल टीम चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस चैंपियनशिप के लिए अंडमान निकोबार स्टेट चेस चैंपियनशिप के खिलाड़ी चयन के लिए पात्र होंगे। टीम का चयन स्टेट चैंपियनशिप की अंतिम रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा। टीम में कुल चार मुख्य खिलाड़ी और एक रिजर्व खिलाड़ी शामिल होंगे। स्टेट चैंपियनशिप की रैंकिंग और विस्तृत नियम AICF की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक खिलाड़ियों को अपनी भागीदारी की सहमति एसोसिएशन के मेल पर 14 फरवरी तक भेजने को कहा गया है।



अंडमान निकोबार द्वीप समूह ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कल फरारगंज में वित्तीय साक्षरता पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम फरारगंज ब्लॉक के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए वित्तीय जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित वित्तीय प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर वित्तीय और कर साक्षरता निदेशालय की सचिव ज्योति सिंह ने विषय पर जानकारी दी। चर्चा के दौरान बुनियादी वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने का महत्व, आयकर रिटर्न, डिजिटल बैंकिंग और धोखाधड़ी से बचाव के तरीकों पर जानकारी दी गई।

